

सेवामें

श्रीमान नोडल अधिकारी महोदय,
जनसूचना पोर्टल राजस्थान

विषय:- जनसूचना पोर्टल के अपडेट के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- सूचना अधिकार अधिनियम 2005, जनहित के लिए सर्वोपरी पोर्टल।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सूचना विभाग की टीम द्वारा जनहित के लिए जनसूचना पोर्टल का निर्माण वर्ष 2019 में हुआ इस पोर्टल से सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का पूरा पालन हो रहा है। इतना ही नहीं इस पोर्टल से सरकार को फायदा भी होगा। प्रायः देखने में आया है कि सरकार की योजनाओं को सरकारी कर्मचारी एवं टैक्स पेयर लोग भी लाभ ले रहे हैं जिससे गरीब लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए आपको निम्न सुझाव प्रेषित किये जा रहे हैं। अगर सुझावों में कोई गलती हो माफ करना।

1. आपकी टीम द्वारा आज दिनांक 19.11.2020 को जनसूचना पोर्टल में कुछ बदलाव किया है उसको पहले कि तरह योजना वाईज ही रखा जावे। <https://jansoochna.rajasthan.gov.in/>
2. सराकर द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाएं आधार कार्ड से जमीन को, पैन कार्ड को, बैंक खाते को, राशनकार्ड को, पहचान पत्र को, जनाधार कार्ड को, ड्राईवींग लाईसेंस, जन्म प्रमाण पत्र को आधार से जोड़ देना चाहिए।
3. सरकार के सभी कर्मचारियों के आधार कार्ड को नियुक्ति आदेश पत्र के साथ लिंक कर देना चाहिए और राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को एस.एस.ओ राजस्थान पोर्टल से जोड़ देना चाहिए। जिससे अगर कर्मचारी सरकारी योजना लाभ लेता है तो पोर्टल पर यह मैसेज आना चाहिए का आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं जिससे आप योजना के लिए पात्र नहीं हैं। ऐसा करने पर महत्वाकांशी योजना एन.एफ.एस.ए. में जो प्रकरण कर्मचारियों के आ रहे हैं उस पर लगाम लगेगी।
4. अगर आधार से प्रत्येक इन्सान के सभी दस्तावेज जोड़ दिये जावें तो पूर्णरूपेण पारदर्शिता आ सकती है।
5. जनसूचना पोर्टल में एक आदमी कितनी योजनाओं का लाभ ले रहा है का ऑप्शन पोर्टल पर आना चाहिए जैसे आधार, पैन, जनआधार, राशनकार्ड, मो0न0 इनमें से कोई एक डालने पर डिटेल आ जानी चाहिए जैसे ईमित्रा पर आता है जैसे –

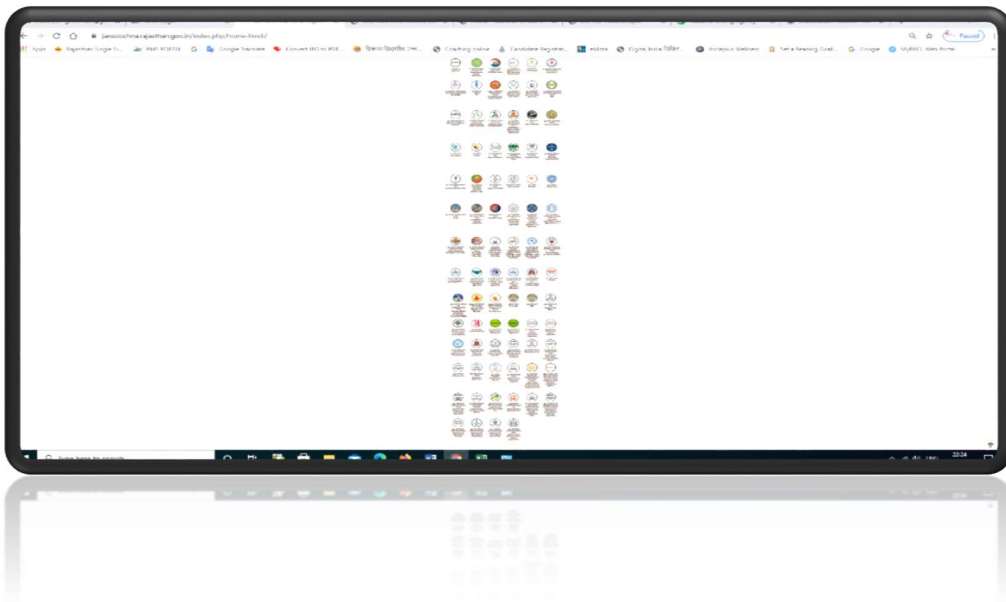
Generic Search

Hof/Member Aadhar		PPO No	
Hof/Member Account Number		Mobile No	
Narega No		Ration No	
District	Please select district	Is Rural	☐ Yes ☐ No
Block	Please select block	Gram Panchayat	Please select Gp
Hof Name		Hof Father Name	
Hof Spouse Name			

- जन्म से लेकर मृत्यु तक एवं सभी डिजिटल दस्तावेज ई-लोकर <https://digilocker.gov.in/> पोर्टल पर प्रदर्शित होने चाहिए इस पोर्टल पर जैसे आधार कार्ड, गैस कनेक्शन, पैन कार्ड, सीबीएसी स्कूल की मार्कशीट आदि प्रदर्शित हो रहे हैं इस पर सभी डिजिटल दस्तावेज प्रदर्शित होने चाहिए।
- जनसूचना का <https://jansoochna.rajasthan.gov.in/index.php/pds/> यही पोर्टल रखे।
- जनसूचना पोर्टल पर Circulars Details में दस्तावेज प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं।
- जन्म प्रमाण पत्र को भी आधार से जन्म के 5 वर्ष के अन्दर तक आधार से लिंक करना चाहिए साथ ही राशनकार्ड में नाम जोड़ने के लिए आधार से ही नाम जुड़ना चाहिए ताकि जनता एवं सरकार को परेशानी नहीं हो और स्वतः ही सीडिंग हो जानी चाहिए। राशन कार्ड में जन्म से तीन वर्ष बाद नाम जोड़ने का ऑप्शन आना चाहिए जैसे मेरी पुत्री कि जन्म दिनांक 01.01.2020 है तो राशन कार्ड में नाम 01.01.2023 में जुड़ना चाहिए तब तक आधार भी बन जायेगा फिर मैं पुत्री के फिंगर 5 साल बाद अपडेट करा लेगें।
- जन्म पर योजनाओं का दरबार खुल जाना चाहिए एवं मृत्यु पर स्वतः ही सभी योजनाएं, बैंक खाता आदि बन्द हो जाना चाहिए एवं अपने परिजन को खाते में जमा पैसा मिल जाना चाहिए।
- कुछ लोग आज भी सरकारी योजनाओं का कुटनीती कर, सरकार को गूमराह कर लाभ ले रहे हैं जिसका पता जनसूचना पोर्टल से पता चला है सरकार को उन पर कार्यवाही करनी चाहिए और जो लाभ ले लिया है उस लाभ का 5 गुना कर वापिस लेना चाहिए साथ ही कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए।
- जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों द्वारा एन.एफ.एस.ए. का लाभ लिया गया था सरकार ने अच्छा कदम उठाया कि 27 रुपये किलो के हिसाब से वसूली कि है।
- कुछ प्रकरण सामने आये कि लोग दुनिया में हैं ही नहीं बल्की परीवार के लोग योजनाओं का लाभ ले रहे हैं जैसे राशनकार्ड से गेहुं, पैन्शिन आदि इसके लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि माना कि मेरी दादाजी कि मृत्यु दिनांक 01.01.2015 को हो गई और उसके पास आधार कार्ड था आधार से सब सेवाएं लिंक थी परन्तु ना तो गेहुं मिलना बन्द हुआ ना ही वृद्धावस्था पैन्शिन रुकी और माना परीवार के पास खाते का एटीएम था जो वृद्धावस्था पैन्शिल खाते में आ रही थी नवम्बर तक आसानी से निकाल ली गई और गेहु भी ले लिया गया क्योंकि वृद्धावस्था पैन्शिल का सत्यापन न होने कि वजह से रुक गई है लेकिन गेहु मिलना नहीं रुका इसके

लिए सरकार को ठोस कदम यह उठाना है कि मृत्यु प्रमाण पत्र को भी आधार से लिंक कर देना चाहिए। जिस दिन मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो जाता है उसी दिन से ही सभी योजना स्वतं ही बन्द हो जानी चाहिए क्योंकि सभी योजनाये आधार से लिंक थी और 21 दिवस में मृत्यु प्रमाण पत्र अवश्य बनाने ही कार्यवाही होनी चाहिए।

14. सरकार को एक डेटा पॉर्टल बनाना चाहिए उस पॉर्टल पर ही आम जन का सारा डेटा होना चाहिए और आधार के.वाई.सी. माध्यम से संबधित पॉर्टल पर डेटा आना चाहिए। और आधार से सभी कागजात को लिंक करना चाहिए।
15. आधार में एक बार ही अपडेट का ऑप्शन होना चाहिए जो भी विशेष परिस्थिति में।
16. डेटा पॉर्टल भी आधार से लिंक कर देना चाहिए।
17. सभी राज सरकारो का अपना-अपना पॉर्टल होना चाहिए जैसे कि राजस्थान का एस.एस.ओ राजस्थान पॉर्टल एवं केन्द्र का सभी राज्यों का एक ही होना चाहिए। जिस प्रकार उमंग पॉर्टल में केन्द्र कि सभी योजनाए सम्मलित है।
18. कुछ योजनाओं के ऐसे प्रकरण सामने आये है कि ऑनलाईन में सबसे बडा घपला सामने आया है जो चिन्ता का विषय है खास कर श्रम विभाग, समाजकल्याण विभाग, कौशल शिक्षा आरएसएलडीसी, चिकित्सा विभाग, और सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि।
19. इस पॉटल पर एसएसओ राजस्थान को लिंक किया जाए और राजस्थान का एक ही पॉर्टल बनाया जाये। एवं हिन्दी में रखा जावे।



<http://jansoochna.rajasthan.gov.in/index.php/home-hindi/> साईट यही रखे।

20. Show entries इस ऑप्शन में 100 के स्थान पर 10000 तक किया जावे ताकि पीडिएफ एक साथ डाउनलोड हो सके।

धन्यवाद